www.sanjanabharati.com | दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित | facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

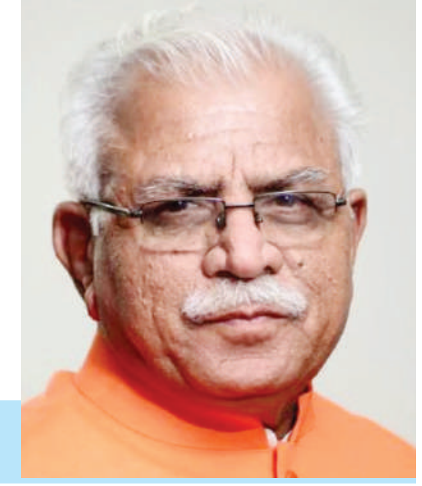

2 लालकिला, दिल्ली बम ब्लास्ट के दूरगामी... | 3 महीनों में पूरी होगी पेंशनरों की पेंशनर सेवा पोर्टल... | 4 हरियाणा में 'मिशन बुनियाद' और 'हरियाणा...

वर्ष: 10 | अंक: 21 | दिल्ली, शुक्रवार, 14 नवम्बर 2025 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

संदिग्धों की तीसरी कार की तलाश में जुटीं जांच एजेंसियां

नई दिल्ली (एजेन्सी)। दिल्ली के लाल किला धमाके के बाद जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। अब जांच एजेंसियां उस तीसरी कार की तलाश में जुटी हैं जो संदिग्धों से जुड़ी बताई जा रही है और फिलहाल लापता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह कार मारुति ब्रेजा हो सकती है जिसे आरोपीयों ने रैकी या भागने के लिए इस्तेमाल किया था। मौजूद जानकारी के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों की कई टीमें दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों में इस तीसरी कार की तलाश कर रही हैं। बता दें कि सोमवार शाम लाल किला इलाके में एक सफेद हुंडई i20 कार में हुए धमाके में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। धमाके के बाद शुरू हुई जांच में पुलिस ने दूसरी संदिग्ध कार, एक लाल फोर्ड इकोस्पोर्ट, फरीदाबाद से बरामद की थी। यह वही कार बताई जा रही है जो मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी से जुड़ी है। इकोस्पोर्ट फरीदाबाद के खंडावली गांव के पास एक फार्महाउस से मिली है, जो आरोपी के एक परिचित का बताया जा रहा है। गौरतलब है कि यह गाड़ी (DL10CK0458) 22 नवंबर 2017 को पंजीकृत हुई थी और इसके मालिक के रूप में डॉ. उमर का नाम दर्ज है। वही डॉ. उमर उस i20 कार के भी मालिक थे जो धमाके के दौरान इस्तेमाल की गई थी।

सरकार की नाकामी से हुआ दिल्ली धमाका: अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश (एजेन्सी)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली में हुए बम धमाके को सरकार की बहुत बड़ी नाकामी करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि खुफिया तंत्र पूरी तरह विफल हो गया, तभी ऐसी घटना हुई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने बिहार चुनाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। यादव बृहस्पतिवार को बरेली पहुंचे जहां वह विधायक अता-उर-रहमान की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे मौकों पर आने से लोगों से मिलने और विचार साझा करने का अवसर मिलता है।

बोत्सवाना ने परियोजना चीता के अगले चरण के लिए भारत को आठ चीते भेंट किए

भारत के साथ संबंधों को मजबूत करते हुए बोत्सवाना की प्रगति में योगदान जारी रखें: द्रौपदी मुर्मु ने भारतीय समुदाय से की अपील

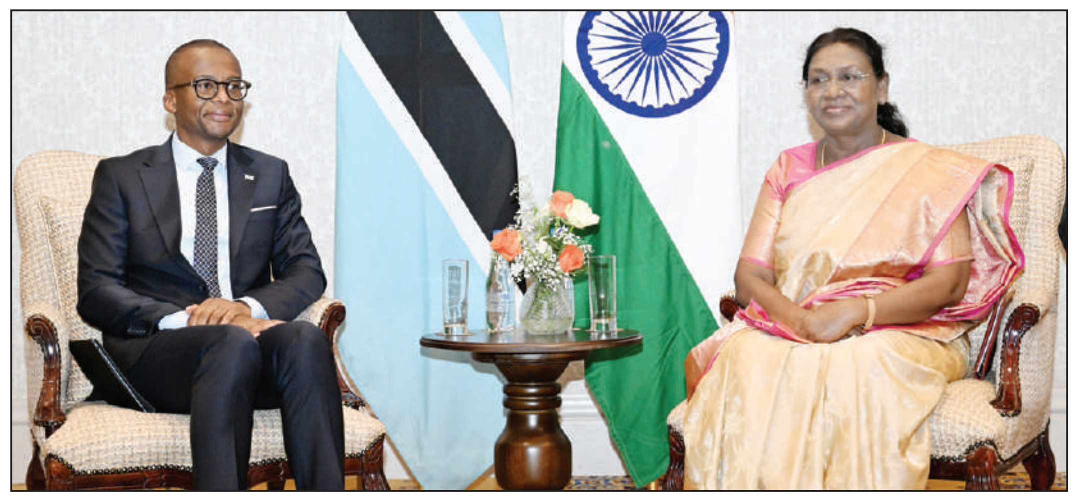

संजना भारती/पीआईबी

नई दिल्ली/बोत्सवाना। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने बोत्सवाना के राष्ट्रपति, महामहिम एडवोकेट ड्यूमा गिदोन बोको के साथ 13 नवंबर को मोकोलोडी नेचर रिजर्व का दौरा किया। दोनों नेताओं ने भारत और बोत्सवाना के विशेषज्ञों की ओर से घांजी क्षेत्र से पकड़े गए चीतों को क्वारंटाइन केंद्र में छोड़े जाने के दृश्य को देखा। यह कार्यक्रम 'प्रोजेक्ट चीता' के तहत बोत्सवाना की ओर से भारत को आठ चीतों के प्रतीकात्मक दान का प्रतीक है। यह आयोजन वन्यजीव संरक्षण में भारत-बोत्सवाना सहयोग में एक नए अध्याय की शुरूआत का प्रतीक है। बाद में, अलग-अलग बैठकों में, बोत्सवाना के उपराष्ट्रपति महामहिम नदाबा नकोसिनथी गौलाथे और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मंत्री माननीय डॉ. फेन्यो बुटाले ने राष्ट्रपति से मुलाकात की।

नई दिल्ली रवाना होने से पहले, राष्ट्रपति ने गाबोरोन में भारत के उच्चायुक्त द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में बोत्सवाना में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया। इस अवसर पर जल शक्ति और रेल राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना तथा सांसद श्री प्रभुभाई नगरभाई वसावा और श्रीमती डी. के. अरुणा भी उपस्थित रहे।

भारतीय समुदाय के उत्साही सदस्यों को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के लोगों को उनके योगदान पर गर्व है। वे भारत के सच्चे सांस्कृतिक राजदूत हैं, जो कड़ी मेहनत, ईमानदारी और सद्भाव के उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारत और बोत्सवाना दोनों की पहचान हैं। उन्होंने उनसे भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए बोत्सवाना की प्रगति में योगदान जारी रखने का आग्रह किया।

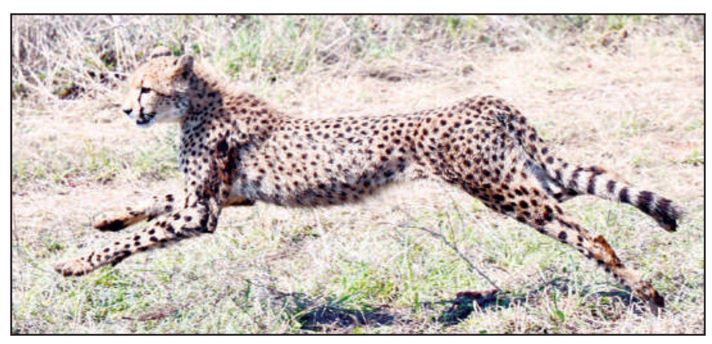

उन्होंने उन्हें ओसीआई योजना और प्रवासी भारतीय दिवस जैसी पहलों का लाभ उठाने और भारत के विकास में अपने अनुभव साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और बोत्सवाना के बीच संबंध विश्वास, सम्मान और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों को बताया कि बोत्सवाना के राष्ट्रपति बोको के साथ चर्चा के दौरान, उन्होंने यह निर्णय लिया कि भारत और बोत्सवाना व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में और अधिक सहयोग करेंगे।

अंगोला और बोत्सवाना जैसे दो अफ्रीकी देशों की सफल यात्रा के बाद, राष्ट्रपति के 14 नवंबर की सुबह नई दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है।

सरकार जल्द ही दिल्ली को एनसीआर शहरों से जोड़ने वाली बस सेवा शुरू करेगी: रेखा गुप्ता

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि उनकी सरकार जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी को विभिन्न एनसीआर शहरों से जोड़ने वाली डीटीसी बस सेवाएं फिर शुरू करेगी। उन्होंने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) द्वारा संचालित एक और अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई, जो कश्मीरी गेट टर्मिनल से सोनीपत बस स्टैंड तक चलेगी। ये इलेक्ट्रिक बसें एयर कंडीशनिंग, सीसीटीवी कैमरे, आपातकालीन बटन और जीपीएस सिस्टम से लैस हैं।

गुप्ता ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही दिल्ली को एनसीआर के आसपास के शहरों से जोड़ने वाली डीटीसी बस सेवाएं फिर शुरू करेगी। उन्होंने सोनीपत के लिए तीन अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले सेवा पखवाड़ा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली और बड़ौत के बीच पहली अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा का उद्घाटन किया था।

गुप्ता ने कहा, नयी डीटीसी इलेक्ट्रिक बसें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। ये बसें यात्रियों के लिए सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेंगी और दिल्ली-सोनीपत मार्ग पर नियमित रूप से चलेंगी, जिससे दोनों शहरों के बीच सुचारू संपर्क सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल गतिशीलता को बढ़ाएगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि अंतरराज्यीय बस सेवाएं कई वर्षों से बंद हैं, जिससे दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के बीच संपर्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

दिल्ली से सोनीपत के लिए बसें सुबह 4.45 बजे, 5.15 बजे, 5.45 बजे तथा शाम में 4.45 बजे, 5.15 बजे और 5.45 बजे चलेंगी।

सोनीपत से दिल्ली के लिए बसें सुबह 7.10 बजे, 7.25 बजे, 8.10 बजे तथा शाम में 7.30 बजे, 8.00 बजे और 8.30 बजे चलेंगी।

जनजातीय गौरव को नई पहचान, योगी सरकार ने बदली वंचित समाज की तस्वीर

संजना भारती संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जनजातीय समाज के जीवन में जो बदलाव आया है, वह सिर्फ योजनाओं का विस्तार नहीं बल्कि सम्मान और अधिकारों की पुनर्स्थापना की एक बड़ी कहानी है। लंबे समय तक उपेक्षित रहे इन समुदायों को योगी सरकार ने न केवल मुख्य धारा में जगह दिलाई बल्कि उनकी परंपराओं, जरूरतों और सपनों को शासन की प्राथमिकता बनाया। मुख्यमंत्री की सोच हमेशा यही रही है कि विकास तभी सार्थक है जब वंचितों को वरीयता मिले और अंत्योदय से सर्वोदय का रास्ता खुले। प्रदेश में थारु, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, राजी, गोंड, बैगा, सहरिया, मुसहर और चेरो जैसी जनजातियों के 11 लाख से अधिक लोगों के जीवन को बदलने के लिए सरकार ने योजनाएं जमीन पर उतारीं। वनाधिकार अधिनियम के तहत आवासीय अधिकार दिए गए, मुख्यमंत्री आवास योजना से वनवासियों को पक्के घर मिले और पीएम जनमन योजना के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली और दूरसंचार जैसी मूलभूत सुविधाओं को सीधे उनके द्वार तक पहुंचाया गया। खास तौर पर बुक्सा जनजाति के 815 परिवारों को हर सुविधा से संतृप्त कर एक नई मिसाल पेश की गई। 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' और 'धरती आबा जनभागीदारी अभियान' ने जनजातीय इलाकों में विकास की असली तस्वीर बदली। 26 जिलों के 517 गांवों तक पहुंचकर सरकार ने कनेक्टिविटी से लेकर आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला, जनधन, किसान सम्मान निधि और विश्वकर्मा जैसी योजनाओं का सैचुरेशन कराया। सोनभद्र, ललितपुर, कुशीनगर, बलरामपुर से लेकर बिजनौर तक इन गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर लगातार बढ़े हैं।

जनजातीय संस्कृति को संजोने पर भी भरपूर जोर दिया गया। बलरामपुर के इमिलिया कोडर में थारू संग्रहालय स्थापित हुआ और मिजार्पुर, सोनभद्र, महराजगंज में नए संग्रहालयों पर तेजी से काम चल रहा है। थारू समुदाय की कला और कौशल को राष्ट्रीय बाजार दिलाने के लिए लखीमपुर खीरी में थारू हस्तशिल्प कंपनी बनाई गई। इसमें जुड़े 371 समूहों को रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड देकर आत्मनिर्भरता की राह दिखाई गई।

दिल्ली में सुरक्षा बढ़ी

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यात्रियों से अतिरिक्त समय लेकर अपनी यात्रा की योजना बनाने का आग्रह करते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद डुम्ब्रे के अनुसार, यात्रियों को असुविधा से बचने और सुरक्षा जांच के दौरान सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डे पर पहले से पहुँचने की सलाह दी जाती। एडवाइजरी के अनुसार, ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम एक घंटा पहले पहुँचना चाहिए।

एससी/एसटी बस्तियों का विकास कर अंत्योदय का संकल्प कर रहे पूरा: इन्द्राज

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की एससी/एसटी बस्तियों में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 65.55 करोड़ रुपये के 114 विकास कार्य अब तक स्वीकृत हो चुके हैं और ये कार्य लगातार पूरे हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त विधानसभाओं के अन्य कार्यों को भी जल्द स्वीकृति दी जाएगी। दिल्ली सरकार के एससी/एसटी कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि एससी/ एसटी बस्तियों का विकास कर सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में अंत्योदय का संकल्प पूरा कर रही है।

एससी/एसटी कल्याण मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय इन बस्तियों की भारी उपेक्षा की गई थी। उस समय न तो कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग होती थी और न ही आवंटित बजट का पूरा उपयोग होता था। इस उपेक्षा के कारण बस्तियां विकास में काफी पीछे रह गईं। अब सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि हर एससी और एसटी बस्ती में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं और लोगों के जीवनस्तर में सुधार लाया जाए।

श्री इन्द्राज ने कहा कि विधानसभाओं की एससी/एसटी बस्तियों में सड़कों और गलियों का निर्माण, नालियों का निर्माण, सामुदायिक भवन, चौपाल व बारात घर का निर्माण, पुनरुद्धार एवं विद्युतिकरण, सीवर लाइन बिछाने व मरम्मत का कार्य, कॉलोनियों के गेट का निर्माण, पार्कों के बॉउंड्री वाल एवं वाक वे का निर्माण, सीसीटीवी लगाने के विकास जैसे कार्य हो रहे हैं।

अब तक तिमारपुर, बवाना, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, त्रिनगर, करोल बाग, पटेल नगर विकास पुरी, बिजवासन, गांधी नगर, नरेला, नांगलोई जाट, शालीमार बाग, मोती नगर, राजौरी गार्डन, पालम, आर के पुरम, त्रिलोकपुरी, गांधी नगर, रोहतास नगर और घोंडा विधानसभाओं में 65.55 करोड़ से अधिक के 114 कार्य स्वीकृत हुए हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य की सभी एससी/एसटी बस्तियों में जनहित में सभी प्रस्तावित बुनियादी सुविधाओं के कार्य पूरे होंगे।

श्री इन्द्राज ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर ने गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण का जो सपना देखा था, उसे सरकार पूरा करने में जुटी है और इन बस्तियों में सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

रेल मंत्रालय ने फिरोजपुर-पट्टी रेल लिंक परियोजना (25.72 कि.मी.) को दी मंजूरी: रवनीत सिंह बिट्टू

- परियोजना से लगभग 10 लाख लोगों को लाभ होगा और लगभग 2.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे
- रेलवे ने पंजाब के मुख्य सचिव को भूमि के शीघ्र अधिग्रहण हेतु पत्र लिखा

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

गोरखपुर। रेल मंत्रालय ने फिरोजपुर-पट्टी रेल लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह पररयोजना कुल 25.72 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी अनुमानित लागत 764.19 करोड़ रुपया है, जिसमें से 166 करोड़ रुपया भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित हैं जो रेलवे द्वारा वहन किए जाएंगे।

मीडिया ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी देते हुए रवनीत सिंह बिट्टू, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने कहा कि यह परियोजना रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे फिरोजपुर और अमृतसर के बीच की दूरी 196 किलोमीटर से घटकर लगभग 100 किलोमीटर रह जाएगी, जबकि जम्मू-फिरोजपुर-फाजिल्का-मुंबई कॉरिडोर की दूरी 236 किलोमीटर कम हो जाएगी। यह परियोजना मालवा और माझा क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होगी, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और लाजिस्टिक दक्षता में सुधार होगा।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए श्री बिट्टू ने कहा कि यह पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक उपहार है। नई रेल लाइन जालंधर-फिरोजपुर और पट्टी-खेमकरण मार्गों को जोड़ेगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट एक सीधा और वैकल्पिक संपर्क स्थापित होगा। यह मार्ग रणनीतिकरक्षा महत्व वाले क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, जिससे सैनिकों, उपकरणों और आपूर्ति की तेज आवाजाही सुनिश्चित होगी। श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि इस परियोजना से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक फायदे होंगे। इससे लगभग 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभा होगा और लगभग 2.5 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगें। यह रेल लाइन प्रतिदिन 2,500 से 3,500 यात्रियों के लिए सुविधा प्रदान करेगी, जिसमें विशेष रूप से छात्रों, कर्मचारियों और ग्रामीण मरीजों को लाभ पहुंचेगा। यह रेल लिंक व्यापार और औद्योगिक विकास हो गति देगा, माल परिवहन लागत को कम करेगा तथा कृषि बाजारों तक पहुँच आसान बनाएगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। नई रेल लाइन अमृतसर, जो एक प्रमुख व्यावसायिक, शैक्षिक और धार्मिक केंद्र है और जहाँ प्रतिदिन एक लाख से अधिक पर्यटक आते हैं, को फिरोजपुर से तेज और मजबूत संपर्क प्रदान करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नया मार्ग विभाजन के समय खोए हुए ऐतिहासिक रूट को पुनर्जीवित करेगा, जिससे फिरोजपुर-खेमकरण की दूरी 294 किलोमीटर से घटकर 110 किलोमीटर रह जाएगी।

मण्डल रेल प्रबंधक/अम्बाला विनोद भाटिया, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर/निर्माण अजय वार्ष्णेय, मुख्य परियोजना प्रबंधक/आर.एल.डी.ए. बलबीर सिंह, अपर मण्डल रेल प्रबंधक/फिरोजपुर नितिन गर्ग एवं ईडीपीजी/रेल राज्यमंत्री धनंजय सिंह भी वहां मौजूद थे।

पंजाब सरकार ने राज्य के ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए जारी किया 332 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक फंड: हरपाल सिंह चीमा

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़। पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को तेज करने, आवश्यक सेवाओं को बेहतर बनाने और ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्यों के लिए 332 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण किश्त जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इसी श्रृंखला में 334 करोड़ रुपये की अगली किश्त दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह में जारी कर दी जाएगी, ताकि ग्रामीण विकास के लिए संसाधनों का निरंतर प्रवाह बना रहे।

पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सत्ता संभालने के पहले दिन से ही विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है। इसी के तहत यह राशि ग्राम पंचायतों के विभिन्न विकास कार्यों, जैसे कि सैनिटेशन बॉक्स की स्थापना आदि के लिए उपयोग की जाएगी।

जारी किए गए फंडों का विवरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 332 करोड़ रुपये की राशि को रणनीतिक रूप से टाइड और अनटाइड फंडों में विभाजित किया गया है ताकि सामान्य स्थानीय विकास और विशेष स्वच्छता कार्य दोनों सुनिश्चित किए जा सकें। उन्होंने बताया कि 156 करोड़ रुपये की ग्रांट अनटाइड फंड के रूप में दी जा रही है, जिसे ग्राम पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी विकास कार्य में उपयोग कर सकती हैं। वहीं 176 करोड़ रुपये की राशि टाइड फंड के रूप में स्वच्छता कार्यों के लिए निर्धारित की गई है। यह संपूर्ण ग्रांट ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद

के बीच 70:20:10 के अनुपात में वितरित की जाएगी। जिला-वार वितरण की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 22 जिलों में कुल 3,329,750,900 रुपये (जिसमें 1,766,319,970 रुपये टाइड फंड और 1,563,430,930 रुपये अनटाइड फंड शामिल हैं) आवंटित किए गए हैं। इनमें सर्वाधिक राशि वाले जिले लुधियाना (टाइड 200,143,127 रुपए, अनटाइड 133,905,292 रुपए), होशियारपुर (टाइड 170,847,451 रुपए, अनटाइड 114305, 089 रुपए और गुरदासपुर (टाइड 165563,924 रुपए, अनटाइड 110770,166 रुपए) हैं। अन्य प्रमुख जिलों में संगरूर, पटियाला, जालंधर, फिरोजपुर, फाज़िल्का, मोगा, शहीद भगत सिंह नगर, श्री मुक्तसर साहिब और तरनतारन शामिल हैं।

पत्रकारों द्वारा केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू के आरोपों पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री की टिप्पणियाँ उनकी 'जानकारी की कमी' और एस एन ए स्पर्श प्रणाली की समझ के अभाव को दशार्ती हैं।

सम्पादकीय

ऋण का दबाव

वैश्विक स्तर पर कई विकासशील एवं अविकसित देशों पर लगातार बढ़ रहे ऋण के दबाव के चलते इन देशों की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव स्पष्टतः दिखाई दे रहा है। इन देशों द्वारा अपने नागरिकों को लम्बे समय तक मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराना जारी रखा गया है एवं यहां की सरकारों द्वारा अपने आय के साधनों में पर्याप्त वृद्धि नहीं की गई है। नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं को ऋण लेकर भी जारी रखना अब इन देशों के लिए आत्मघाती निर्णय साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज यह देश दिवालिया होने के मुहाने पर खड़े हैं तथा इन्हें अपना सामान्य प्रशासन चलाने के लिए खर्च करने हेतु भी ऋण लेना पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक आंकलन के अनुसार, अक्टूबर 2025 में वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद का 98.9 प्रतिशत सार्वजनिक ऋण बकाया है, जो वर्ष 2030 तक 102.3 प्रतिशत तक बढ़ जाने की सम्भावना है। विभिन्न देशों के सार्वजनिक ऋण, आय से अधिक खर्च करने की प्रवृति, अधिक ब्याज दर, आय में कम वृद्धि होना, आदि कारकों के चलते लगातार बढ़ता जा रहा है। विकासशील एवं अविकसित देश अपनी आय में वृद्धि नहीं कर पाते हैं परंतु, उन्हें अपने नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खर्च लगातार बढ़ाते रहना होते हैं। इन्हीं कारणों के चलते श्रीलंका, अर्जेंटीना, सूडान, ग्रीस, मालदीव, सेनेगल, आदि देशों में तो आर्थिक आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी एवं विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थानों द्वारा इन देशों की मदद के लिए आगे आना पड़ा था, अन्यथा यह देश लगभग दिवालिया घोषित होने की स्थिति में पहुच गए थे। वर्ष 2025 में विश्व के प्रथम 10 देशों में, जिनका ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत सबसे अधिक है, शामिल हैं– जापान (229.6 प्रतिशत), सूडान (221.5 प्रतिशत), सिंगापुर (175.6 प्रतिशत), ग्रीस (146.7 प्रतिशत), बहरीन (142.5 प्रतिशत), इटली (136.8 प्रतिशत), मालदीव (131.8 प्रतिशत), अमेरिका (125 प्रतिशत), सेनेगल (122.9 प्रतिशत) एवं फ्रान्स (116.5 प्रतिशत)। ग्रीस, घाना, हैती, मोजांबीक, पाकिस्तान, जाम्बिया, फिलिपींस, श्रीलंका, कीन्या, अर्जेंटीना, आदि देशों द्वारा अधिक मात्रा में लिए गए ऋण के चलते इनकी वित्तीय स्थिति डावांडोल हो चुकी है। इन देशों द्वारा अपने खर्चों को व्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया था एवं केवल जनता को मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध कराना लम्बे समय तक जारी रखा गया था तथा साथ में आय बढ़ाने के साधनों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इससे इन देशों का बजटीय घाटा लगातार बढ़ता रहा तथा मजबूरी में इन्हें अपने साधारण सरकारी कामकाज चलाने के लिए भी ऋण लेते रहना पड़ा है। वर्ष 2001 में युगांडा में वित्तीय संकट खड़ा हो गया था एवं उस समय पर युगांडा अपने सामान्य खर्चों को जारी रखने के स्थिति में भी नहीं था। भारत में भी कुछ राज्य फ्रीबी के नाम पर कुछ ऐसी योजनाएं चला रहे हैं जिनके अंतर्गत राज्य की जनता के बिजली एवं पानी के बिल समय समय पर माफ किये जा रहे हैं। किसानों, बुजुर्गों एवं मातृशक्ति के बैंक खातों में सीधे ही कुछ राशि प्रति माह जमा की रही है। जबकि, इन राज्यों की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि इनके बजट इस अतिरिक्त खर्च को वहन कर सकें। कुछ राज्य तो आज मजबूरी में इन योजनाओं को चलायमान बनाए रखने के लिए बाजार से ऊंची ब्याज दर पर ऋण भी लेने लगे हैं। जिसका प्रभाव इन राज्यों की वित्तीय स्थिति पर विपरीत रूप से पड़ रहा है। यदि समय पर ये राज्य नहीं चेते एवं इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं किया तो ये राज्य अपने भारी भरकम ऋणों पर ब्याज अदा करने में चूक करने की ओर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर जब राज्यों की आर्थिक स्थिति की चर्चा होती है तो इसका असर राज्यों के विकास और इन राज्यों में निवास कर रहे नागरिकों के जीवन पर भी पड़ता है। लोकलुभावन राजनीति इन राज्यों की वित्तीय स्थिति को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन में भी राज्यों की वित्तीय स्थिति को लेकर कई गंभीर पहलु और सवाल खड़े किए गए हैं। विशेष रूप से पंजाब, केरल, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल आदि राज्य बढ़ते कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं और इन राज्यों की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। हाल ही के समय में पंजाब, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल एवं बिहार की वित्तीय सेहत बहुत बिगड़ी है। सभी राज्यों की वित्तीय सेहत का विस्तार से आकलन करने पर ध्यान में आता है कि कई राज्यों द्वारा अनियंत्रित रूप से चलाई जा रही मुफ्त योजनाओं, लोकलुभावन घोषणाओं, अत्यधिक सब्सिडी देने एवं पुरानी पेंशन योजना बहाली से इन राज्यों की वित्तीय सेहत बहुत बुरी तरह से बिगड़ रही है। राज्य, विशेष रूप से सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से, कई लोकलुभावन घोषणाएं करते हैं जैसे कि बिजली एवं पानी मुफ्त में उपलब्ध कराने का वादा, उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करने का वादा आदि जिसका सीधा असर राज्य की माली हालत पर पड़ता है। पंजाब की आर्थिक स्थिति पूर्व में ही बहुत गम्भीर अवस्था में पहुंच चुकी है फिर वहां नई सरकार ने किए गए चुनावी वादे अर्थात मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के अपने वादे पर कार्य करना शुरू कर दिया है जिससे पंजाब की स्थिति निश्चित रूप से और अधिक बिगड़ने जा रही है और पंजाब को ऋण की किश्त एवं ऋणों पर ब्याज अदा करने हेतु भी ऋण लेना पड़ रहा है।

जयंती

जवाहरलाल नेहरू

जन्म: 14 नवम्बर, 1889; मृत्यु: 27 मई, 1964) भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के महान सेनानी एवं स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री (1947–1964) थे। जवाहर लाल नेहरू, संसदीय सरकार की स्थापना और विदेशी मामलों में 'गुटनिरपेक्ष' नीतियों के लिए विख्यात हुए। 1930 और 1940 के दशक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से वह एक थे।

पुण्यतिथि

सी. के. नायडू

जन्म–13 अक्टूबर, 1895, नागपुर, महाराष्ट्र; मृत्यु–14 नवम्बर, 1967, इन्दौर, भारत की क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान रहे थे। सी. के. नायडू उस उम्र तक क्रिकेट खेलते रहे, जिसके बारे में सोचना भी आज के खिलाड़ियों के लिए दिवास्वप्न है। नायडू की उस समय की फिटनेस आज के उन खिलाड़ियों के लिए एक सबक है, जो दूसरे तीसरे मैच के बाद ही चोटिल हो जाते हैं। 37 साल की उम्र में जब आज खिलाडी रिटायर होने लगते है, तब सी. के. नायडू ने टेस्ट मैंच खेलना शुरू किया था। वह 68 साल तक फिट रहकर क्रिकेट खेलते रहे थे।

कल मिलेंगे

पत्नी–सुनो जी, आपको नहीं लगता
भगवान ने मुझे फुर्सत में बनाया होगा
पति–फालतू के काम फुर्सत में ही होते हैं
उसके बाद पति की हुई जमकर कुटाई.....

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।

RNI No. : DELHIN/2016/70240

Phone No.: 9871221635

E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com

(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

लालकिला, दिल्ली बम ब्लास्ट के दूरगामी मायने को ऐसे समझिए

देखा जाए तो लालकिला दिल्ली बम ब्लास्ट एक बड़ी आतंकवादी साजिश का छोटा और अनहोनी रूप से हुआ विस्फोट था, जिसने सुरक्षा की जरूरत और आतंकवाद के खतरे को फिर से उभारा है। इसकी जांच अभी भी चल रही है और जिम्मेदारों को न्याय के अंतर्गत लाया जाएगा। कहना न होगा कि इस बम ब्लास्ट के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव गहरे और बहुआयामी रहे हैं

-कमलेश पांडेय

लालकिला दिल्ली बम ब्लास्ट के सुरक्षात्मक मायने बेहद गम्भीर हैं। इससे आतंकवादियों के दुःशाहस और षड्यंत्रकारियों की हिमाकत का पता चलता है। इसलिए इसका मतलब कई स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला, यह ब्लास्ट दिल्ली के राष्ट्रीय प्रतीक और ऐतिहासिक स्थल लाल किले के पास हुआ, जहां 12 लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए। इससे देश के पर्यटन व्यवसाय को प्रभावित करने की पुनः नापाक कोशिश हुई है।

बेशक इस हमले को एक बड़ी आतंकी साजिश माना जा रहा है, जिसका संबंध पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़ा है। भले ही यह हमला आत्मघाती मिशन नहीं था, बल्कि गलती या जल्दबाजी में विस्फोटक उपकरण के असंपूर्ण निर्माण के कारण हुआ, जिससे उसका विनाशकारी प्रभाव सीमित रहा। वहीं, जांच में इस बात का पता चला है कि आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद ने इस साजिश को अंजाम दिया, जो गिरफ्तारी के डर से विस्फोटक को कहीं और ले जाने या नष्ट करने की कोशिश कर रहा था।

निःसंदेह यह धमाका पैनिक अटैक का हिस्सा था और समय रहते सुरक्षा जांच और सतर्कता ने एक बड़ा खतरनाक हादसा होने से रोक लिया। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां बधाई की पात्र हैं। बहरहाल, इस ब्लास्ट ने देश को आतंकी खतरे की गम्भीरता के प्रति जागरूक किया और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को भी परखा। वहीं, इस घटना के बाद कई स्थानों पर छापेमारी और गिरफ्तारी हुई हैं, ताकि ऐसे आतंकवादी मॉड्यूल को पूरी तरह खत्म किया जा सके।

देखा जाए तो लालकिला दिल्ली बम ब्लास्ट एक बड़ी आतंकवादी साजिश का छोटा और अनहोनी रूप से हुआ विस्फोट था, जिसने सुरक्षा की जरूरत और आतंकवाद के खतरे को फिर से उभारा है। इसकी जांच अभी भी चल रही है और जिम्मेदारों को न्याय के अंतर्गत लाया जाएगा। कहना न होगा कि इस बम ब्लास्ट के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव गहरे और बहुआयामी रहे हैं। इस घटना के बाद न केवल कई देशों ने भारत के प्रति संवेदना जताई, बल्कि वैश्विक कूटनीतिक विमर्श में सुरक्षा, आतंकवाद और नागरिक सुरक्षा संबंधी मुद्दे चर्चा में आ गए हैं.

जहां तक अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ का सवाल है तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान, ईरान, मलेशिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मोरक्को, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव सहित एशिया, यूरोप, मध्य-पूर्व के अनेक देशों ने दुख और संवेदना जताई है। वहीं, अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए नई दिल्ली में यात्रा और सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया और पर्यटन स्थलों में सतर्कता बरतने को कहा। कई देशों, जैसे मलेशिया, ने संभावित आतंकवादी कृत्य की सख्त निंदा की और आम नागरिकों को निशाना बनाने की आलोचना की।

जहां तक इसके कूटनीतिक और सुरक्षा संबंधी प्रभाव का प्रश्न है तो ब्लास्ट के बाद भारत के कई महत्वपूर्ण दूतावास क्षेत्रों, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। क्योंकि नई दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी भी है। लिहाजा, वैश्विक स्तर पर भारत के आंतरिक सुरक्षा सहयोग के प्रति महत्वपूर्ण देशों द्वारा भी समर्थन व्यक्त किया गया। वहीं, आतंकवाद-विरोधी सहयोग और सूचना साझा करने के मुद्दे पर भारत को अतिरिक्त समर्थन मिलने की संभावना है।

जहां तक इस घटना के क्षेत्रीय और वैश्विक संदेश का सवाल है तो इस घटनाक्रम ने भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित अन्य देशों (श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव) को भी आशंकित कर दिया, जिन्होंने न केवल संवेदना जताई, बल्कि अपनी आंतरिक सतर्कता बढ़ा दी। वहीं, वैश्विक नेताओं ने भारत की सरकार से घटनाक्रम के जांच पर भरोसा जताया और पीड़ित परिवारों को साहस बनाए रखने का संदेश दिया।

लालकिला बम ब्लास्ट ने पुनः आतंकवाद पर अन्तरराष्ट्रीय विमर्श को तेज कर दिया है। पश्चिमी देशों और कई मुस्लिम राष्ट्रों ने दोहराया कि आतंकवादी कृत्यों के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता। अंतरराष्ट्रीय मीडिया और राजनयिक चैनलों ने क्षेत्रीय सुरक्षा प्रयोजनों के लिए सूचना-साझाकरण और निगरानी तंत्र को और मजबूत करने के संकेत दिए हैं। इस घटना से भारत और अन्य देशों में सुरक्षा-विचार, आतंकवाद-निरोध, नागरिक सुरक्षा और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के एजेंडे में तीव्रता आई है।

वहीं, लालकिला दिल्ली बम ब्लास्ट के घायलों और मृतकों के परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने विशेष सहायता और मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपया की एकमुश्त राशि दी जाएगी। स्थायी रूप से विकलांग (अक्षम) हुए पीड़ितों को 5 लाख रुपया का मुआवजा मिलेगा। गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपया की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साधारण चोटिल हुए व्यक्ति को 20,000 रुपया तक की सहायता मिल सकती है।

इसके अतिरिक्त, सभी घायलों का इलाज सरकारी खर्च पर किया जाएगा, जिसमें सरकारी या निजी अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि राहत राशि शीघ्र जारी की जाए और प्रक्रिया में पीड़ितों को कोई परेशानी न हो। यह मुआवजा आयकर से मुक्त रहेगा, ताकि लाभार्थियों को पूरी राशि प्राप्त हो सके। इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पीड़ित परिवारों के सहारा और इलाज को पहली प्राथमिकता दी है।

वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक
(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

हाईवे के किनारे खड़ी गाड़ियों पर सुप्रीम टिप्पणी

भारत में सड़क हादसे एक गंभीर चिंता का विषय हैं, जहां हर साल बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 4,80,583 से अधिक दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1,72,890 से अधिक मौतें हुईं और 4,62,825 लोग घायल हुए। देश में प्रतिदिन लगभग 1,316 हादसे और 474 मौतें होती हैं, यानी हर घंटे लगभग 20 जानें जाती हैं

-डॉ. आशीष वशिष्ठ

देश भर में नेशनल हाईवे व शहर के अंदर व आउटर में संचालित होटलों, ढाबों के किनारे भारी वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए रोड पर जहां-तहां वाहनों को खड़ा कर दिया जाता है। सड़क किनारे खड़े ऐसे वाहन अन्य वाहन चालकों और यात्रियों के लिए यमदूत साबित हो रहे हैं। बीती 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के फालौदी और तेलंगाना के श्रीकाकुलम के सड़क हादसों में 37 लोगों की मौत पर सुओ मोटो कार्रवाई करते हुए सड़क सुरक्षा की गंभीर खामियों पर चिंता जताई है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान हाईवे के किनारे अवैध ढाबों पर भी चिंता जताई। कहा कि इन ढाबों पर आने वालों की गाड़ियां हाईवे पर खड़ी रहती हैं, जिनसे हादसे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से सड़क किनारे मौजूद ढाबों और सड़क मेंटेनेंस की स्थिति पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की बेंच ने कहा कि दो सप्ताह के भीतर एक सर्वे कराया जाए, जिससे यह पता चल सके कि कितने ढाबे राजमार्गों के किनारे ऐसे क्षेत्रों में बनाए गए हैं जो इस तरह की सुविधाओं के लिए अधिसूचित नहीं है यानी अवैध ढाबों के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। यातायात के नियमों के मुताबिक, हाईवे के किनारे सड़क पर ट्रक व अन्य वाहन खड़े नहीं किए जा सकते हैं।

शीर्ष न्यायालय की टिप्पणी के आलोक में बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास के नाम पर हमने सरपट वाहन दौड़ने वाली सड़कें तो बना दी, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया कि यात्रा दुर्घटनाओं से निरापद कैसे रहे। यह हृदय विदारक होता है कि सड़कों के निर्माण में तकनीकी खामियों, ट्रकों की अराजकता तथा राजमार्ग के अवरोधों के चलते परिवार के परिवार असमय काल कवलित हो जाते हैं। जिम्मेदार विभाग और सरकार की चतुराई यह होती है कि वह समस्या के मूल में जाने की बजाय जांच और फौरी कार्रवाई में लग जाता है। इन हादसों की जवाबदेही तय नहीं की जाती। हर हादसे के बाद पुरानी तंत्र पुरानी स्क्रिप्ट को दोहराता है।

आमतौर पर किसी भी बड़े हादसे में शिकार हुए यात्रियों की संख्या का ही जिक्र होता है और सरकार मुआवजे की घोषणा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है। अधिक से अधिक हमारे विमर्श का मुद्दा यह होता है कि दोषी कौन था? कौन सा ड्राइवर लापरवाही से वाहन चला रहा था, वह नशे में था या उसे नींद की झपकी लग गई। या फिर वाहन में तकनीकी खामी की वजह से हादसा हुआ। लेकिन वास्तव में हम उन तकनीकी व वास्तविक खामियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो दुर्घटना का कारण बनती हैं। एक ओर जहां सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा की गई चूक होती हैं, वहीं सड़कों के किनारे बेतरतीब बने ढाबे भी होते हैं, जहां अकसर ट्रक चालक अपने वाहन गलत ढंग से खड़े कर देते हैं। लेकिन हर हादसे में कहीं न कहीं ऐसे कारण जरूर होते हैं, जो दुर्घटना की तात्कालिक वजह बनते हैं। लेकिन अक्सर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कारक को अनदेखा करने की वजह से भविष्य में ऐसी ही दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति होने की आशंका बलवती होती है।

भारत में सड़क हादसे एक गंभीर चिंता का विषय हैं, जहां हर साल बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 4,80,583 से अधिक दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1,72,890 से अधिक मौतें हुईं और 4,62,825 लोग घायल हुए। देश में प्रतिदिन लगभग 1,316 हादसे और 474 मौतें होती हैं, यानी हर घंटे लगभग 20 जानें जाती हैं। दुनिया के केवल 1 प्रतिशत वाहन भारत में हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली वैश्विक मौतों का 11 प्रतिशत हिस्सा यहीं है।

यह विडंबना ही है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर जगह-जगह टोल संग्रह केंद्रों के जरिये टैक्स तो खूब वसूले जाते हैं, लेकिन राजमार्गों को दुर्घटनाओं से निरापद बनाने के लिये गंभीर प्रयास नहीं होते। कुकुरमुत्तों की तरह सड़कों का अतिक्रमण करते ढाबों पर लगाम नहीं लगाई जाती। गंभीरता से पड़ताल नहीं होती है कि क्या सड़क निर्माण में ठेकेदार ने सभी तकनीकी मानकों का पालन किया है? सबसे ज्यादा बड़े वाहन ढाबों पर खड़े नजर आते हैं। रात व दिन में यहां वाहन एक के पीछे एक खड़े रहते हैं। रात के समय तो आलम और भी भयंकर होता है, यहां से निकलने में भी डर बना रहता है। नियमित चेकिंग न होने और चालान न होने की वजह से यहां हादसे का डर बना रहता है। छुटपुट मामले तो आये दिन होते रहते हैं।बरसात के मौसम में इन ढाबों के पास हादसे की अधिक आशंका रहती है। ट्रक मिट्टी में खड़े होकर हाईवे पर आते हैं तो मिट्टी सड़क पर जमा हो जाती है। बरसात में इस मिट्टी से फिसलकर बाइक सवार हादसे का शिकार हो जाते हैं। इस के अलावा कई बार ट्रकों या अन्य लोडिंग वाहनों में उनकी क्षमता से अधिक माल भरा होता है। मुख्यता लोहे के सरिये, गर्डर आदि जो लोडिंग की लंबाई में न आते हुए पीछे तक निकले रहते हैं। इस तरह के वाहन भी हादसों का कारण बनते हैं।

यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से लाखों रुपये रुपये प्रचार-प्रसार पर बहाया जाता है। इसके बावजूद सड़क सुरक्षा के नियम निर्देश कहीं भी धरातल पर देखने को नहीं मिलते हैं। गोष्ठियों और सेमिनारों में तो वाहन चालकों को नियमों का पाठ पढ़ाया जा जाता है लेकिन हाईवे ट्रक, डीसीएम, कंटेनर या अन्य वाहन चालकों को समझाने वाला कोई नहीं है। देश में सैकड़ों लोगों की मौत सड़क के किनारे गलत तरीके से खड़े ट्रक से वाहनों के टकराने से होती है, लेकिन दोषी ट्रक चालक को कड़ी सजा नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर वाहन चालकों को भी गति सीमा में रहने तथा अन्य सावधानियों का सख्ती से पालन करना चाहिए। सरकारों का दायित्व भी बनता है कि राजमार्गों पर रफ्तार की सीमा के नियमन के साथ बाधामुक्त सफर भी सुनिश्चित करें।

निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की जवाबदेही बनती है कि राजमार्गों को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिये नियमित जांच-पड़ताल की जाती रहे। ताकि निर्दोष लोगों के बेमौत मरने का सिलसिला खत्म हो सके। इन विभागों व मंत्रालयों का जिम्मा सिर्फ टोल वसूलना ही नहीं है बल्कि सड़कों को सुरक्षित बनाना भी इनकी जवाबदेही है। निश्चित रूप से सड़क के निर्माण की गुणवत्ता तथा उसे दुर्घटना मुक्त बनाने के लिये उच्च सुरक्षा मानकों का क्रियान्वयन भी उतना जरूरी है। इसके अलावा सख्त कानून व निगरानी के जरिये ट्रकों व भारी वाहनों को सड़क के किनारे खड़े करने पर रोक लगायी जाए। भारत में हर साल हजारों सड़क हादसे होते हैं. ज्यादातर में लापरवाही जिम्मेदार होती है। सुप्रीम कोर्ट का ये कदम सरकार और अधिकारियों पर दबाव डालेगा। इससे हाईवे सुरक्षित होंगे, ढाबे नियंत्रित जगह पर चलेंगे और ट्रक पार्किंग के लिए अलग जगह बनेगी। आम जनता की जान बचाने के लिए ये बड़ा फैसला साबित हो सकता है।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

1400 मौतों के लिए शेख हसीना को मौत की सजा! बांग्लादेश में 17 नवंबर को आएगा फैसला

(एजेन्सी)।

बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण सोमवार (17 नवंबर) को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाएगा। उन पर पिछले साल ढाका में हुए घातक विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराधों से संबंधित पाँच आरोप हैं। अभियोजकों ने अपदस्थ प्रधानमंत्री, जो भारत में हैं, के लिए मृत्युदंड की माँग की है। छात्रों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई के कारण उन्हें अपदस्थ कर दिया गया और वे भारत भाग गईं।

गौरतलब है कि पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल, जो अपदस्थ अवामी लीग सरकार का हिस्सा थे और तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून पर भी न्यायाधिकरण में मुकदमा चलाया गया था। हसीना और कमाल दोनों पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया क्योंकि अदालत ने उन्हें "भगोड़ा" घोषित कर दिया था।

संयुक्त राष्ट्र ने फरवरी में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि पिछले साल ढाका में हुई हिंसा में लगभग 1,400 लोग मारे गए होंगे। इस बीच, देश के स्वास्थ्य सलाहकार ने कहा कि 800 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 14,000 घायल हुए। आईसीटी-बीडी के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने हसीना के लिए मौत की सजा की माँग की है। उन्होंने कहा कि अपदस्थ प्रधानमंत्री 1,400 लोगों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि चूँकि यह मानवीय रूप से संभव नहीं है, इसलिए हम कम से कम एक सजा की माँग करते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की खामोशी, पाकिस्तान में होने लगी हाई लेवल मीटिंग!

(एजेन्सी)।

लाल किले के पास धमाका भारत के दिल में जख्म देने की कोशिश और पीछे वही पुराना नाम जैश मोहम्मद जी हां वही संगठन जो पाकिस्तान की गोद में पलता है भारत के खिलाफ जहर उगलता है और हर बार किसी ना किसी नापाक साजिश को रचता है पर इस बार खेल अलग नजर आ रहा है और पीएम मोदी का इरादा भी साफ है। प्रधानमंत्री मोदी भूटान से लौटे और एक पल की देरी किए बिना सीधे अस्पताल पहुंच गए। घायलों का हौसला बढ़ाया और फिर सीसीएस की मीटिंग भी ली।

दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के ज़िम्मेदारों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस घटना को आतंकी हमला घोषित कर दिया, और प्रधानमंत्री मोदी ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार जोर देकर कहा कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को कड़ी सजा मिलेगी।

पाकिस्तान इस बार अपने आप को बचा नहीं पाएगा। हम ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और इस बात को भी आप समझिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कहा कि जो मिलिट्री एक्शन हमने लिया जिस तरीके से आतंक के ठिकानों को हमने नेस्तोनाबूत किया वो ऑपरेशन सिंदूर का मात्र एक एक्सप्रेशन है। मल्टीपल लेवल पे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। पीएम मोदी की खामोशी बस एक बात कही जा रही है कि इसके पीछे जो कोई भी है हां उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसको छोड़ा नहीं जाएगा। प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि दिल्ली हमले और लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद सहित पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों के बीच संबंध हैं।

ईडन गार्डन्स में टीम इंडिया पिछली गलतियों से सबक लेकर उतरेगी

(एजेन्सी)।

कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुक्रवार से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। मुकाबले से पहले भारत के सहायक कोच रयान टेन डोशेटे ने कहा है कि टीम इस बार पिछली गलतियों से सबक लेकर उतरेगी। बता दें कि पिछले साल भारत को घरेलू टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था, जिसने टीम को गहराई से सोचने पर मजबूर किया था। मौजूद जानकारी के अनुसार, भारत ने हाल ही में वेस्टइंडीज को 2-0 से हराकर सीरीज अपने नाम की है और अब टीम का ध्यान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत दर्ज करने पर है। दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान में खेली गई टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ की थी, जिसमें उनके स्पिन गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था। केशव महाराज, साइमन हार्मर और सेनुरन मुथुसामी ने मिलकर पाकिस्तान के 40 में से 33 विकेट हासिल किए थे। मुथुसामी को पहले टेस्ट में शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया था।

गौरतलब है कि भारत की पिछली घरेलू सीरीज में न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने पूरी भारतीय बल्लेबाजी को मुश्किल में डाल दिया था। उस समय अजाज पटेल ने 15 विकेट, मिशेल सैंटनर ने 13 विकेट और ग्लेन फिलिप्स ने 8 विकेट हासिल किए थे। यह वही सीरीज थी जिसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी टेस्ट प्रारूप से संन्यास की घोषणा की थी।

टेन डोशेटे ने कहा कि टीम अब इस अनुभव से सीख चुकी है। उन्होंने कहा, हमने न्यूजीलैंड सीरीज से सबक लिया है और स्पिन के खिलाफ खेलने के लिए खास योजनाएं बनाई हैं। हमें पता है कि उपमहाद्वीप में खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। हमने अपने खेल में सुधार लाने पर ध्यान दिया है और इस सीरीज को लेकर टीम का आत्मविश्वास ऊंचा है। उन्होंने आगे कहा कि दक्षिण अफ्रीका की टीम पिछले कुछ महीनों में काफी बेहतर हुई है और उसे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के लिए श्रेय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, पिछले 9-10 महीनों में दक्षिण अफ्रीका ने बेहतरीन क्रिकेट खेला है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराकर अपनी क्षमता साबित की है। उनकी स्पिन गेंदबाजी इस सीरीज को और रोमांचक बना देती है।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह दो टेस्ट मैचों की सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जा रही है, और दोनों ही टीमें इस सीरीज से अंक हासिल कर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में हैं। ऐसे में ईडन गार्डन्स का पहला टेस्ट रोमांच से भरा रहने वाला है और भारतीय टीम अपने घरेलू दर्शकों के सामने मजबूत प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

अर्जुन, प्रज्ञानानंदा और हरिकृष्णा का शानदार प्रदर्शन

(एजेन्सी)। गोवा में चल रहे FIDE शतरंज विश्व कप 2025 में अब भारतीय खिलाड़ियों की संख्या घटकर तीन रह गई है। टूर्नामेंट की शुरूआत 206 खिलाड़ियों के साथ हुई थी, जिनमें से 24 भारत के थे। लेकिन अब केवल अर्जुन एरिगैसी, आर. प्रज्ञानानंदा और पेंटाला हरिकृष्णा ही अगले दौर की दौड़ में बने हुए हैं। बुधवार को भारत के प्रणव वी और कार्तिक वेंकटारमन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। बता दें कि चौथे राउंड के पहले गेम में अर्जुन एरिगैसी और हंगरी के ग्रैंडमास्टर पीटर लेको के बीच महज 20 चालों में ड्रॉ हो गया था। दूसरे गेम में भी दोनों खिलाड़ियों ने तेज शुरूआत की और 36 चालों के बाद मैच बराबरी पर समाप्त हुआ। लेको ने मैच के बाद कहा कि उन्हें अर्जुन की ओपनिंग से कोई डर नहीं था, हालांकि उन्होंने माना कि जब अर्जुन तेजी से चाल चलते हैं तो दबाव जरूर बनता है। वहीं, बोर्ड नंबर तीन पर आर. प्रज्ञानानंदा का मुकाबला रूस के डेनियल डुबोव से हुआ। डुबोव ने एक बार फिर रचनात्मक ओपनिंग खेली, लेकिन प्रज्ञानानंदा ने बेहतरीन सटीकता से खेलते हुए मुकाबला बराबरी पर समाप्त कर दिया। दूसरी ओर, अनुभवी खिलाड़ी हरिकृष्णा ने स्वीडन के ग्रैंडमास्टर निल्स ग्रांडेलियस के खिलाफ शानदार रक्षात्मक खेल दिखाया। हालांकि ग्रांडेलियस को कुछ मौकों पर बढ़त मिली, पर हरिकृष्णा ने अपने अनुभव के दम पर मैच ड्रॉ करा लिया। गौरतलब है कि अब तीनों भारतीय खिलाड़ी गुरुवार को होने वाले टाईब्रेकर राउंड में उतरेंगे, जहां मुकाबले छोटे समय नियंत्रण के साथ खेले जाएंगे।

ललित केशरे की कंपनी ने शेयर बाजार में दी शानदार शुरूआत, पहले दिन 30% की बढ़त

(एजेन्सी)।

बेंगलुरु की ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म Groww की मूल कंपनी बिलियनब्रेन गेराज वेंचर्स, ने बुधवार को शेयर बाजार में शानदार शुरूआत की है। कंपनी के लिस्टिंग डे पर निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है।

इसी बीच, बेंगलुरु के एक स्टार्टअप फाउंडर सुधांशु ने ग्रो ऐप के सीईओ ललित केशरे का एक पुराना संदेश साझा किया, जिसमें केशरे ने लिखा था हे सुधांशु, कभी मिलते हैं, बताना अगर समय मिले। सुधांशु ने इस संदेश का स्क्रीनशॉट एक्स (पूर्व ट्विटर) पर साझा करते हुए बताया कि आईपीओ से करीब साढ़े तीन महीने पहले ललित उनसे मैटिक्स के बारे में बात करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि ललित और उनका बेटा उस ऐप के नियमित यूजर हैं और उन्होंने उनसे कई बातें सीखी हैं। सुधांशु ने लिखा कि "उन्होंने बताया था कि वे आज भी रोज दो घंटे Groww ऐप का इस्तेमाल करते हैं। इससे मैंने सीखा कि अपने प्लेटफॉर्म के प्रति जुनून और यूजर रिटेंशन ही सबसे महत्वपूर्ण है।"

गौरतलब है कि Groww की शुरूआत 2016 में हुई थी और आज यह भारत के सबसे बड़े रिटेल ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स में से एक बन चुका है। बता दें कि इस फिनटेक यूनिकॉर्न को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला का भी समर्थन मिला है।

मौजूद जानकारी के अनुसार, कंपनी का शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 112 रुपये प्रति शेयर पर खुला और कुछ ही समय में 124 रुपये तक पहुंच गया। जबकि इसका इश्यू प्राइस 100 रुपये तय किया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी स्टॉक ने मजबूत शुरूआत की और 114 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ, जो इश्यू प्राइस से करीब 14 प्रतिशत ज्यादा था।

दिन के अंत तक Groww के शेयरों में और तेजी देखने को मिली। NSE पर यह 128.85 रुपये पर बंद हुआ, जो IPO प्राइस से 28.85% ज्यादा है। वहीं इरए पर यह 130.94 रुपये तक पहुंच गया, यानी 30.94% की बढ़त दर्ज की है। कंपनी की इस शानदार शुरूआत ने निवेशकों का विश्वास और बढ़ा दिया है और बाजार में यह संदेश दिया है कि मजबूत यूजर बेस और भरोसेमंद प्रोडक्ट किसी भी स्टार्टअप को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।

जूनियर एनटीआर ने लॉन्च किया मोगली 2025 का टीजर

(एजेन्सी)। डेब्यू एक्ट्रेस साक्षी मेढोलकर की पहली फिल्म मोगली 2025 का टीजर यंग टाइगर जूनियर एनटीआर ने लॉन्च किया, जिससे फिल्म industry में साक्षी की एंट्री को जबरदस्त पहचान मिली है। टीजर लॉन्च साक्षी के लिए बेहद भावुक और यादगार पल रहा, क्योंकि तेलुगु सिनेमा से उनका भावनात्मक जुड़ाव काफी पुराना है। साक्षी ने इस अनुभव को अपने करियर का सबसे बड़ा क्षण बताया। वे कहती हैं, मैंने तेलुगु फिल्में देखकर भाषा सीखी और आज मेरे पसंदीदा स्टार जूनियर एनटीआर गरु ने मेरी डेब्यू फिल्म मोगली 2025 का टीजर लॉन्च किया। यह दिन हमेशा याद रहेगा। टीजर रिलीज के दौरान जूनियर एनटीआर ने साक्षी की स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय क्षमता की भी तारीफ की, जो उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा साबित हुई। मोगली 2025 का निर्देशन नेशनल अवॉर्ड विजेता संदीप राज ने किया है। फिल्म का निर्माण टीजी विश्व प्रसाद और कृति प्रसाद ने पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले किया है। फिल्म 12 दिसंबर 2025 को विश्वभर में रिलीज होगी। फिल्म में साक्षी एक ऐसी युवती का किरदार निभा रही हैं जो सुन और बोल नहीं सकती। यह चुनौतीपूर्ण भूमिका उनसे विशेष भाव-प्रकटन और गहरी संवेदनशीलता की मांग करती थी। इस बारे में साक्षी कहती हैं, इस किरदार ने मुझे खामोशी की ताकत समझाई और एक कलाकार के रूप में मुझे निखारा। टीजर में साक्षी की झलक को दर्शकों ने ध्यान से नोट किया है, और उनकी परफॉर्मेंस को लेकर सोशल मीडिया पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं। खूबसूरत जंगल पृष्ठभूमि, दमदार संगीत और पौराणिक संकेतों के बीच साक्षी की उपस्थिति कहानी की भावनात्मक परत को मजबूत बनाती है।

महीनों में पूरी होगी पेंशनरों की पेंशनर सेवा पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रियाः हरपाल सिंह चीमा

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को घोषणा की कि नए लॉन्च किए गए पेंशनभोगी सेवा पोर्टल पर राज्य के पेंशनभोगियों का पंजीकरण तीन महीने के भीतर पूरा हो जाएगा। उन्होंने यह घोषणा एस ए एस नगर स्थित जिला प्रशासनिक परिसर में आयोजित तीन दिवसीय पेंशनभोगी सेवा मेले के उद्घाटन के दौरान की। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि 13 से 15 नवंबर तक चलने वाला यह मेला पंजाब के सभी ज़िलों में पेंशनभोगियों को पोर्टल पंजीकरण में सहायता के लिए आयोजित किया जा रहा है।

पहले ही दिन, राज्य भर में 5,320 से अधिक पेंशनभोगियों ने पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया। सुचारू पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए, वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि वित्त विभाग और पेंशन वितरण बैंकों के अधिकारी सभी ज़िला-स्तरीय कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी तकनीकी समस्या का मौके पर ही समाधान किया जा सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज़िला कोषागार कार्यालयों, पेंशन वितरण बैंकों, सेवा केंद्रों और सेवा केंद्रों द्वारा घर-घर पहुँचाई जाने वाली सेवाओं के माध्यम से पंजीकरण सहायता निरंतर उपलब्ध रहेगी।

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान तकनीकी कठिनाइयों का सामना करने पर भी पेंशन वितरण निर्बाध रूप से जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 3 नवंबर को लॉन्च किए गए पेंशनभोगी सेवा पोर्टल का उद्देश्य पेंशनभोगियों के घरों तक सीधे व्यापक पेंशन संबंधी सेवाएँ पहुँचाना है। शुरूआत में, यह पोर्टल पाँच प्रमुख सेवाएँ प्रदान करेगा, जिनमें जीवन प्रमाण मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना, पेंशन को पारिवारिक पेंशन में बदलने के लिए आवेदन, छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) अनुरोध, पेंशन संबंधी शिकायतों का पंजीकरण, व्यक्तिगत विवरण अपडेट करना या बदलना इत्यादि शामिल हैं।

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रवासी भारतीय (एनआरआई) पेंशनभोगियों को वर्तमान में पेंशनभोगी सेवा पोर्टल के प्रारंभिक रोलआउट से बाहर रखा गया है और वे मौजूदा प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जारी रखेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में एनआरआई पेंशनभोगियों के लिए भी इसी तरह की डिजिटल सेवाएँ शुरू की जाएँगी। पोर्टल के शुभारंभ के बाद किसी भी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए, कोषागार एवं लेखा निदेशालय ने पेंशन और नई पेंशन योजना के लिए एक समर्पित वॉर रूम स्थापित किया है। इसके अलावा, पेंशनभोगियों की समस्याओं और शिकायतों में सहायता के लिए तीन हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2148, 0172-2996385 0172-2996386 सक्रिय किए गए हैं। ये हेल्पलाइन सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक संचालित होती रहेंगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नई दिल्ली दौरा

राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं के मद्देनजर विद्युत निकासी के सुदृढ़ीकरण को लेकर हुई अहम चर्चा

संजना भारती संवाददाता

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास को नए आयाम देने की दिशा में शहरी विकास, ऊर्जा, जल परियोजनाओं एवं कौशल विकास से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की।

मुख्यमंत्री शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से भेंट के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में राजस्थान में भारत के सौर ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने की अपार संभावनाओं को देखते हुए विद्युत निकासी के सुदृढ़ीकरण को लेकर सार्थक चर्चा की गई।

बैठक में अवगत कराया गया कि किसानों के हित में टॉवर बेस मुआवजा दर को डी.एल.सी. दर के 400 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है जबकि कॉरिडोर मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों में 30 प्रतिशत, नगरपालिका क्षेत्रों में 45 प्रतिशत तथा नगर निगम क्षेत्रों में 60 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। बैठक में यह भी बताया गया कि ए.टी. एण्ड सी. हानियों में लगातार कमी आ रही है। इसी क्रम में जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम अब 15 प्रतिशत के स्तर से नीचे आ चुके हैं। साथ ही, आर.डी.एस.एस. योजना के क्रियान्वयन की गति में सुधार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। साथ ही, उन्होंने जयपुर मेट्रो के चरण-2 की डीपीआर स्वीकृति को लेकर भी विस्तृत चर्चा की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल से मुलाकात के दौरान प्रदेश में जल आपूर्ति, जल संचयन सहित जल परियोजनाओं पर वार्ता की। दोनों के मध्य फिरोजपुर फीडर रिलाइनिंग एवं रामजल सेतु लिंक परियोजना की प्रगति को लेकर सार्थक चर्चा हुई। इस दौरान प्रदेश में चल रहे कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की सफलता की सराहना की गई।

इसके बाद मुख्यमंत्री शर्मा ने केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी से भी मुलाकात की। इस दौरान शर्मा एवं चौधरी के मध्य केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान को स्किल डवलपमेंट हब बनाने से जुड़े रोडमैप पर चर्चा की गई।

पंजाब सरकार द्वारा 'मिशन चढ़दी कला' के तीसरे चरण के तहत राहत वितरण प्रक्रिया जारी

लगातार तीसरे दिन 6 करोड़ रुपये से अधिक की मुआवजा राशि वितरित

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व में जनकल्याण और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रति पंजाब सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज लहरागागा में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित 280 निवासियों को 1.02 करोड़ रुपये के मुआवजा स्वीकृति पत्र वितरित किए।

सभा को संबोधित करते हुए मंत्री श्री गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के उन नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, जो बाढ़ या भारी वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, वन एवं वन्यजीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज जिला पठानकोट के नरोट जैमल सिंह में

विभिन्न गाँवों के बाढ़ प्रभावित लोगों को 45 लाख रुपये की मुआवजा राशि वितरित की और यह दोहराया कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।

राहत वितरण प्रक्रिया के तीसरे चरण के लगातार तीसरे दिन, पंजाब सरकार ने मिशन चढ़दी कला के तहत अपनी व्यापक पहल जारी रखते हुए राज्यभर के बाढ़ प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की।

सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी दी कि जिला फिरोजपुर में विधायक रणबीर सिंह भुल्लर ने गांव बंडाला में 732 बाढ़ प्रभावित परिवारों को 4.85 करोड़ रुपये के मुआवजा स्वीकृति पत्र वितरित किए। आप हलका इंचार्ज एडवोकेट हरसिमरन सिंह घुंमण ने भुल्लथ (कपूरथला) क्षेत्र के प्रभावित परिवारों को 7.20 लाख रुपये के मुआवजा स्वीकृति पत्र सौंपे। उल्लेखनीय है कि पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने बाढ़ प्रभावित परिवारों को सबसे अधिक मुआवजा प्रदान किया है। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक प्रभावित परिवार तक राहत पारदर्शी ढंग से पहुँचे।

जानकारी के अनुसार, क्षतिग्रस्त घरों के लिए वित्तीय सहायता को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति घर कर दिया गया है, जबकि फसल नुकसान के लिए प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है-जो देश में अब तक दिया गया सबसे अधिक फसली मुआवजा है।

इसके अलावा, प्रभावित परिवारों की आजीविका बहाली के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रति दुग्धारू पशु 37,500 रुपये, प्रति गैर-दुग्धारू पशु 32,000 रुपये, प्रति बछड़ा 20,000 रुपये तथा प्रति पोल्ट्री पक्षी 100 रुपये का मुआवजा प्रदान किया जा रहा है।

वाटरशेड महोत्सव का राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह

जल स्रोतों के पुनरुद्धार से भूजल स्तर बढ़ेगा-शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री

संजना भारती संवाददाता

जयपुर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश में कई स्थानों पर भूजल स्तर काफी नीचे पहुंच गया है, भूमि में नमी नहीं होने से वनस्पतियां उत्पादित नहीं हो रही हैं और मिट्टी के निरंतर कटाव से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए हमें बारिश के पानी को एकत्र कर भूजल रिचार्ज बढ़ाने के लिए जल ग्रहण विकास के कार्य करने होंगे। साथ ही, पेड़-पौधे लगाकर मिट्टी का कटाव रोकने एवं नदियों, तालाबों तथा परम्परागत जल स्त्रोतों के पुनरुद्धार के कार्य मिशन वाटरशेड के तहत करने होंगे। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आज से उण्डवा में राज्य स्तरीय वाटरशेड महोत्सव एवं मिशन जल ग्रहण पुनरुत्थान कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है।

दिलावर गुरुवार को कोटा जिले की खैराबाद पंचायत समिति के उण्डवा गांव में वाटरशेड महोत्सव के राज्य स्तरीय समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी 159 जल ग्रहण विकास परियोजनाओं में इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर आमजन में जागरूकता पैदा की जाएगी और वाटर शेड का महत्व समझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल स्त्रोतों के पुनरुद्धार से भूजल स्तर बढ़ेगा, भूमि में नमी से हरियाली बढ़ेगी और जानवरों के लिए चारा उत्पादित होगा। इससे प्रदेश की तस्वीर भी बदलेगी। उन्होंने सभी का आह्वान किया कि मिशन जल

ग्रहण पुनरुत्थान एवं वाटर शेड महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लें।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि विलायती बबूल जूलीफ्लोरा ने प्रदेश में 500 प्रकार की वनस्पतियों को समाप्त कर दिया है, गहरी जड़ें होने के कारण विलायती बबूल प्रतिदिन 30 लीटर पानी सोंखता है और इससे भूजल स्तर काफी तेजी से नीचे जाता है। उन्होंने कहा कि इससे निकलने वाली जहरीली गैसों से बीमारियां फैलती हैं एवं मिट्टी भी अनुपजाऊ हो जाती है। देशी वनस्पतियों को खा रहे इस राक्षस को पूरे प्रदेश से हटाने के लिए विलायती बबूल हटाओ-चारागाह बचाओ अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायतें अपने कोष से पैसा खर्च कर जूलीफ्लोरा को जड़ से उखाड़कर नष्ट करें। उन्होंने कहा कि जहां विलायती बबूल है वहां से उसे समूल नष्ट कर उन जगहों पर चरागाहों का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नदी, तालाब एवं परंपरागत जल स्त्रोतों के पुनरुद्धार अभियान के तहत रामगंजमंडी क्षेत्र की वर्षों पुरानी पाटली नदी को पुनर्जीवित किया गया है। इस नदी के पानी से 50 हजार बीघा से अधिक जमीन सिंचित होगी। दिलावर ने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है जहां देसी वनस्पतियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बीज बैंक बनाए गए हैं। उन्होंने इस अवसर पर मोबाइल बीच बैंक मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। इसके माध्यम से वानस्पतिक बीज बैंकों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हर गांव को स्वच्छ रखने के लिए पंचायतों को प्रतिमाह एक लाख रुपये उपलब्ध कराए हैं। जिन पंचायतों में जनसंख्या अधिक है वहां 5 लाख रुपये तक दिए जा रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि हर गांव में प्रतिदिन झाडू लगे और कचरा गाड़ी घरों से कचरा उठाए यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और ईमानदारी से कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

कार्यक्रम में निदेशक जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण मोहम्मद जुनैद ने कहा कि पूरे देश में अकृषि भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करने, गिरते भू-जल में सुधार एवं किसानों की आय में वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-2.0 शुरू की गई है। इसमें भारत सरकार द्वारा पूरे देश में 2000 करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति दी गई है इनमें खैराबाद पंचायत समिति में भी 11 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गंगा नगर एवं बांसवाड़ा को छोड़कर सभी जिलों में 159 परियोजनाएं चल रही हैं।

भारत सरकार द्वारा इस अवसर पर जल ग्रहण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली वोटर शेड मिशन की विजेता 15 परियोजनाओं को 20-20 लाख रुपये की पुरस्कार राशि के चेक वितरित किए गए। इनमें उदयपुर जिले की पंचायत समिति कुराबड़, पंचायत समिति कोटड़ा, पंचायत समिति ऋषभदेव, पंचायत समिति नया गांव, पंचायत समिति भींडर एवं पंचायत समिति वल्लभ नगर, राजसमंद जिले की पंचायत समिति भीम, झालावाड़ जिले की पंचायत समिति बकानी एवं झूंझूनूं जिले की पंचायत समिति बुआना की परियोजना को पुरस्कार वितरित की गई।

14 से 27 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। व्यापार मेले के नाम से प्रसिद्ध भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) का 44वां संस्करण 14 से 27 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। इस वार्षिक आयोजन से भारत और विदेशों की विविध कलाओं, शिल्पों और उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक मंच मिलता है। इस वर्ष का थीम "एक भारतः श्रेष्ठ भारत" है, जो राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विविधता और आर्थिक विकास की भावना को दशार्ता है।

भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा आयोजित इस मेले में इस वर्ष बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य होंगे। इसके अलावा झारखंड फोकस राज्य होगा। मेले के दौरान प्रति दिन राज्य दिवस समारोह, सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आईआईटीएफ-2025 में हरियाणा पैवेलियन आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। हरियाणा पैवेलियन परंपरा और तकनीक का एक मनोरम मिश्रण होगा जहां एक थीम आधारित स्वागत क्षेत्र और डिजिटल थीम वाली दीवार, सूरजकुंड मेला, गीता महोत्सव और विरासत पर्यटन स्थलों जैसे प्रतीकों के माध्यम से हरियाणा के सांस्कृतिक गौरव को उजागर किया जाएगा। पवेलियन में एआर-आधारित सेल्फी पॉइंट और होलोबॉक्स एआई "ताऊ" इंस्टॉलेशन जैसे उन्नत इंस्टॉलेशन एक भविष्यवादी स्पर्श जोड़ेंगे, जो राज्य की कहानियां, सामान्य ज्ञान और उपलब्धियों को एक संवादात्मक डिजिटल गाइड प्रदान करेंगे।

खानपुर थानाध्यक्ष ने फरार चल रहे एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार

थानाध्यक्ष रंजीत कुमार चौधरी ने गिरफ्तार अभियुक्त को भेजा जेल

संजना भारती संवाददाता
अर्जुन कुमार झा

समस्तीपुर। खानपुर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार चौधरी ने बीती रात पुलिस फोर्स के साथ गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के मुजारी गाँव में छापामारी कर समस्तीपुर न्यायालय से निर्गत-NBW वारंट जिसका CR-न0 761/2024-TR-न0 416/2025 में फरार चल रहा अभियुक्त (1) राजेन्द्र पासवान पिता स्वर्गीय बालेश्वर पासवान -ग्राम-मुजारी-थाना खानपुर जिला समस्तीपुर को छापामारी के क्रम में घर से ही गिरफ्तार कर थाना लाया गया।वही गिरफ्तार अभियुक्त के बारे में पूछने पर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त राजेन्द्र पासवान-पिता-स्वर्गीय बालेश्वर पासवान-ग्राम-मुजारी-खानपुर ने समस्तीपुर न्यायालय से निर्गत NBW वारंट में घर छोड़ कर फरार चल रहा था। जिसे गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस फोर्स के साथ बीती अभियुक्त को घर से ही गिरफ्तार कर थाना लाया गया। जिसे गिरफ्तारी कागजात तैयार कर थाना के पुलिस पदाधिकारी व चौकीदार के साथ उचित अभिरक्षा में सरकारी वाहन से माननीय न्यायालय समस्तीपुर में उपस्थापन हेतु भेजा गया है।

आज आएगा चुनाव का परिणाम, लगेंगे सारे के कयासो पर पूर्ण विराम

संजना भारती संवाददाता

अकबरनगर। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सारे कयासों पड़ कल रिजल्ट आने के बाद विराम लग जाएगा। मतगणना से पहले दिन भर चुनाव परिणाम के आने की चर्चा होती रही। लोग अपने-अपने अंदाज से हर एक प्रत्याशी को जीता और हरा रहे हैं। सुल्तानगंज विधानसभा में बंपर वोटिंग होने के बाद जहां भी जाइये अगर चार लोग हैं तो जीत-हार पर ही चर्चा कर रहे हैं। मतदान खत्म हुए 48 घंटे बीत चुके हैं लेकिन गांव-गांव में अभी भी चुनाव की गूंज है। चौराहों पर खड़ी भीड़, चाय की दुकानों से उठती भाप और चौपालों में गूंजती बहस से हर जगह एक ही सवाल तैर रहा है कि इस बार किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा।मतदान खत्म हुआ और छोटे-छोटे चौराहे मानो न्यूज रूम बन गया। लोग, दुकानदार, ग्राहक सभी एंकर, प्रवक्ता, राजनीतिक विशेषज्ञ बन गए। किसी ने चाय की चुस्की ली, किसी ने पान चबाया और हार-जीत के जोड़-घटाव पर बातचीत शुरू हो गई।

सुबह होते ही अखबारों पर टिकी आंखेंः सुबह गांव की गलियों और दुकानों पर बैठे लोग अखबार से चिपके मिले। चुनावी पन्नों पर लोगों की नजरें टिकी रही। कोई आंकड़े गिनता रहा, कोई चर्चा करते दिखे। कोई बोले, दस हजार खाते में आने के बाद महिलाओं ने इस बार कमाल कर दिया। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने जमकर मतदान किया। युवा ने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं ने रिकार्ड तोड़ मतदान किया। अबकी तस्वीर बदल सकती है। दुकान पर बैठे बुजुर्ग बोले, इस बार जात का हिसाब भी थोड़ा गड़बड़ हुआ है। कुछ वोट रिश्तेदारी में भी चले गए होंगे। पास ही बैठा युवा कहता है, अब तो लोग चेहरा देखकर वोट देते हैं, जात देखकर नहीं। पुरानी पीढ़ी के तजुर्बे और नई पीढ़ी की सोच में टकराव है लेकिन दोनों में उम्मीद एक समान है।

हमारे बूथ पर अपने लोगों को दिया वोट, जीत पक्कीः गांव के चाय दुकान पर बैठे लोगों ने कहा कि हमारे बूथ पर तो सब अपने ही लोग थे, अबकी जीत पक्की है। पास ही बैठे दूसरे शख्स ने बात काटी, अरे, आप भूल गए क्या? सामने वाले की जाति का इलाका है वो, वहां से मामला पलट सकता है। इस बार लोगों ने वोट विकास के नाम पर दिया है।

श्री हिंदू तख्त के नेतृत्व में नई चेतना की लहर

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजेश कुमार

पंचकूला। आज का समय वह है जब समाज को अपने संस्कारों, परंपराओं और धर्म की मूल भावना से जोड़ने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। इसी उद्देश्य को लेकर श्री हिंदू तख्त के अध्यक्ष महंत प्रवीण कुमार के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में एक नई जागृति की लहर दौड़ पड़ी है।

महंत श्री प्रवीण कुमार का संकल्प है-हर घर में धर्म की लौ जलानी है, हर मन में सनातन का सम्मान जगाना है। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर हजारों लोग श्री हिंदू तख्त के साथ जुड़ रहे हैं और समाज को एक सशक्त दिशा देने का कार्य कर रहे हैं।

महंत प्रवीण कुमार का संगठनात्मक कौशल और आध्यात्मिक नेतृत्व लोगों को आकर्षित कर रहा है। उनके नेतृत्व में न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक स्तर पर भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर जिले, हर गाँव में श्री हिंदू तख्त की शाखाएँ सक्रिय होकर समाज सेवा, धर्म प्रचार और संस्कृति संरक्षण में जुटी हैं। लोग उनके विचारों से प्रभावित होकर संगठन का हिस्सा बनना अपने जीवन का सौभाग्य समझ रहे हैं।

इस पूरे अभियान में मीडिया एडवाइजर सुमित कुमार की भूमिका भी अत्यंत सराहनीय है। सुमित कुमार अपनी मीडिया रणनीति, संवाद कौशल और समर्पण भावना से संगठन के संदेश को आम जन तक पहुँचाने का कार्य बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय मीडिया के माध्यम से श्री हिंदू तख्त की गतिविधियों को लोगों तक पहुँचाकर जन-जन में नई चेतना का संचार किया है। आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुका है श्री हिंदू तख्त। चाहे वह युवा वर्ग हो, महिलाएँ हों या समाज के वरिष्ठजन-सभी इस संगठन से जुड़ने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। लोगों में यह भावना जागृत हो रही है कि धर्म केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि एक जीवनशैली है जो हमें आत्मबल, अनुशासन और एकता का संदेश देती है।

महंत श्री प्रवीण कुमार का कहना है कि हमारा उद्देश्य किसी के विरुद्ध नहीं, बल्कि अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व की रक्षा करना है। यही सकारात्मक सोच लोगों के हृदय में जगह बना रही है। सुमित कुमार और पूरी टीम दिन-रात समाज में जागरूकता फैलाने में लगी हुई है।

श्री हिंदू तख्त अब केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका है-जो हर हिंदू के आत्मगौरव, सम्मान और एकता का प्रतीक बनकर उभर रहा है। आने वाले समय में यह लहर और भी प्रबल होगी, और पूरा प्रदेश इस जागरण यात्रा का साक्षी बनेगा।

हरियाणा में 'मिशन बुनियाद' और 'हरियाणा सुपर सौ' के जागरूकता अभियान की हुई शुरूआत

■ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास से सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के सपने हो रहे साकार

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। हरियाणा शिक्षा विभाग ने पूरे प्रदेश में मिशन बुनियाद और हरियाणा सुपर सौ कार्यक्रमों के ब्लॉक व स्कूल स्तर पर जागरूकता अभियान की शुरूआत की। इन दोनों महत्वाकांक्षी योजनाओं का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मध्यवर्गीय व गरीब परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर मार्गदर्शन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अवसर प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए मिशन बुनियाद और सुपर सौ जैसी

मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी

बेहतरीन योजनाएं चला कर सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के स्वप्नों को सफलता के पंख लगा दिए हैं। हरियाणा सरकार के प्रयास से प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन की नींव रखी जा रही हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा का कहना है कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा आर्थिक स्थिति के कारण पीछे न रह जाए।

गौरतलब है कि हरियाणा के तात्कालिक मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2017 में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में "सुपर सौ" योजना की शुरूआत की थी। उनकी योजना की बदौलत हरियाणा के सरकारी स्कूल के विद्यार्थी आज देश के नामी गिरामी सरकारी संस्थानों में एमबीबीएस व आई आई टी की पढ़ाई कर अपना भविष्य संवार रहे हैं। पूरे देश

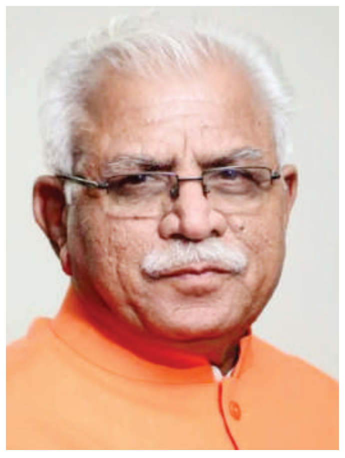
पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा एवं वर्तमान केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल

में हरियाणा की "सुपर सौ" व "मिशन बुनियाद" योजना की प्रशंसा हो रही है।

शिक्षा मंत्री हरियाणा महीपाल सिंह ढांडा

शिक्षाविदों ने कहा कि इनसे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी है।

प्रदेश के शिक्षा मंत्री महीपाल सिंह ढांडा ने सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए अनेक लाभकारी योजना शुरू की है उनमें "सुपर सौ" व "मिशन बुनियाद" विशेष है।

शिक्षा मंत्री हरियाणा के ग्रामीण तबके व गरीब घरों की स्थिति से भली प्रकार से वाकिफ है गरीबों के घर में भी प्रतिभावान विद्यार्थियों की कमी नहीं होती, लेकिन अवसरों की कमी के कारण वे बेस

सुपर सौ डायरेक्टर नवीन मिश्रा

कीमती हीरे झोपड़ी में पलने वाले प्रतिभावान विद्यार्थी देश में अपनी चमक बिखरने से महफूज रह जाते थे। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूल के गरीब विद्यार्थियों के लिए "सुपर सौ" व "मिशन बुनियाद" के रूप में मदद का हाथ बढ़ाया है। जिसकी चारों ओर प्रशंसा हो रही है।

सुपर सौ के निदेशक नवीन मिश्रा ने बताया कि मिशन बुनियाद के अंतर्गत 8वीं कक्षा के विद्यार्थी और सुपर सौ के अंतर्गत 10वीं कक्षा के विद्यार्थी चयन परीक्षा के माध्यम से उन्नत कोचिंग और संसाधनों का लाभ ले रहे हैं। इन अभियानों ने अब तक हजारों बच्चों के जीवन में नई दिशा दी है और यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा।

मिशन बुनियाद निदेशक प्रदीप कुमार सेसरवाल

मिशन बुनियाद के निदेशक प्रदीप कुमार सेसरवाल ने कहा कि राज्यभर में आज ए.बी.आर.सी. व बी.आर.पी. की बैठकों में अभियान की रणनीति तय की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर विद्यालय में जाकर विद्यार्थियों को इन कार्यक्रमों की जानकारी दें, वीडियो दिखाएँ और वहीं पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाएँ।

सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण व शहरी, दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थी बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए सही दिशा, वातावरण और सहयोग मिले।

पंजीकरण हेतु लिंक: www.registration.buniyaadhry.com

मिशन बुनियाद और हरियाणा सुपर सौ कार्यक्रमों का विस्तृत समय-सारणी घोषित

हरियाणा शिक्षा विभाग ने मिशन बुनियाद और हरियाणा सुपर सौ कार्यक्रमों के लिए आगामी सत्र 2026-28 की विस्तृत समय-सारणी जारी कर दी है। जिलेवार कार्यक्रम की शुरूआत कैथल जिले से होगी: जिसमें

18 नवम्बर 2025 को सिवन ब्लॉक में अभियान चलेगा।

इसके बाद 26 नवम्बर को राजौंद, 2 दिसम्बर को कलायत, 10 दिसम्बर को पूंडरी, 12 दिसम्बर को चीका गुहला और 15 दिसम्बर को कैथल ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

मिशन बुनियाद (2026-28) के अंतर्गत पंजीकरण 13 नवम्बर 2025 से प्रारंभ होकर 16 दिसम्बर 2025 तक चलेगा। विद्यालय स्तर पर अभियान 13 नवम्बर से शुरू होगा, जबकि ब्लॉक स्तर पर 14 नवम्बर से। प्रथम स्तर की प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड 17 दिसम्बर को जारी होगा और परीक्षा 24 दिसम्बर 2025 को आयोजित की जाएगी। परिणाम 20 जनवरी 2026 को घोषित किया जाएगा। द्वितीय स्तर की परीक्षा 30 जनवरी 2026 को होगी, जिसका परिणाम 25 फरवरी को आएगा। तृतीय स्तर की परीक्षा और ओरीएंटेशन प्रोग्राम 3 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होंगे। काउंसलिंग 7 मई को शुरू होकर कक्षाएं 15 मई 2026 से आरंभ होंगी।

हरियाणा सुपर सौ (2026-28) कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों का पंजीकरण 13 नवम्बर 2025 से शुरू होकर 9 फरवरी 2026 तक चलेगा। प्रवेश परीक्षा के प्रथम चरण का एडमिट कार्ड 6 फरवरी को जारी किया जाएगा और परीक्षा 11 फरवरी 2026 को होगी। परिणाम 15 मार्च को घोषित होगा। द्वितीय चरण की परीक्षा 2 अप्रैल 2026 को और परिणाम 30 अप्रैल 2026 को आएगा। इसके बाद चयनित विद्यार्थियों की कक्षाएं 5 मई 2026 से प्रारंभ होंगी।

शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि इन दोनों योजनाओं के माध्यम से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा, मार्गदर्शन और अवसर मिलें ताकि वे भविष्य की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

धान घोटाले पर भाकियू का प्रदर्शन, रतन मान बोले-काली जांच से सच्चाई दबा रही सरकार

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। प्रदेश में धान खरीद प्रक्रिया में हुए घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने करनाल में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष रतन मान के नेतृत्व में सैकड़ों किसान काले कपड़े पहनकर जाट धर्मशाला से पैदल मार्च करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

रतन मान ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन घोटाले की काली जांच के नाम पर सच्चाई दबा रहे हैं। उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एसीएस आईएएस डी. सुरेश पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन्हें ही जिम्मेदारी देकर सरकार ने घोटाले को बढ़ावा दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो प्रदेशभर में आंदोलन छेड़ा जाएगा।

भाकियू नेताओं ने बताया कि विभागीय आंकड़ों के अनुसार 2025 में धान की पैदावार 25-30% घटने के बावजूद 18 लाख 22 हजार मीट्रिक टन की फर्जी आमद दिखाकर करीब 4 हजार करोड़ रुपये का गेट पास घोटाला किया गया है। किसानों ने आरोप लगाया कि मिलर्स और अधिकारियों की मिलीभगत से उन्हें एमएसपी से 200-300 रुपये प्रति क्विंटल कम भुगतान हुआ, जिससे लगभग 175 करोड़ रुपये की ठगी हुई।

भाकियू ने मांग की कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की जाए और किसानों का बकाया अंतर तुरंत चुकाया जाए। रतन मान ने कहा कि यह लड़ाई किसानों की मेहनत, इज्जत और अधिकारों की है अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया, तो यह आंदोलन राज्यव्यापी रूप ले लेगा।

सरकार किसानों की समस्याओं का करें समाधान: सेवा सिंह आर्य

संजना भारती संवाददाता

असन्ध। किसानों की मासिक बैठक गुरुद्वारा डेहरा साहिब में ब्लॉक प्रधान जीवन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में किसानों को सम्बोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सेवा सिंह आर्य ने कहा कि गांव में आवारा पशुओं की संख्या कम होने की बजाय लगातार बढ़ रही है जिससे किसान परेशान है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि आवारा पशुओं का प्रबंध करें ताकि कोई भी आवारा पशु बेसहारा ना रहे और किसान की फसल बर्बाद होने से बच जाए। उन्होंने कहा कि समय पर किसानों को खाद्य और दवाईयां उपलब्ध कराई जाए ताकि वे अपनी फसलों का सही उत्पादन कर सके और नुकसान से बच सके।

आर्य ने कहा कि सही समय पर दवाईयां उपलब्ध होने से किसान फसलों को कीटों और बीमारियों से बचा सकते है। आर्य ने कहा कि किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करें ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

इस अवसर पर सुखवंत सिंह, शोभा सिंह, कुलवंत सिंह, अंग्रेज सिंह, जनरैल सिंह, दर्शन सिंह, गुरदयाल सिंह, भीम सिंह, लखविंदर सिंह, तरलोक सिंह, कुलदीप सिंह, जोगिंद्र सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।

गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता और धर्म की स्वतंत्रता के लिए दिया महान बलिदान: मंत्री रणबीर गंगवा

■ हिंद की चादर लाइट एंड साउंड शो का हुआ भव्य आयोजन

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। हरियाणा आर्ट एवं कल्चर विभाग की ओर से जिला प्रशासन के सौजन्य में कैथल के आरकेएसडी कॉलेज परिसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित एक अत्यंत भव्य हिंद की चादर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया। इसमें लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूंडरी विधायक सतपाल जांबा व भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी ने भाग लिया। सभी गणमान्य व्यक्तियों ने गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को मानवता और धर्म की स्वतंत्रता के लिए दिया गया एक महान बलिदान बताया और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।

मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि यह कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर जी के जीवन आदर्शों, त्याग, बलिदान और अमर विरासत को समर्पित है। गुरु जी ने धर्म, मानवता और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनका बलिदान राष्ट्र की अस्मिता और एकता का प्रतीक है। उन्होंने किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं, बल्कि मानव मात्र की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर सिंह जी का जन्म 1621 में हुआ। उनका जीवन साहस, धैर्य और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। हिंद की चादर केवल एक रूपक नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्रतिज्ञा है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर त्याग की एक नई परिभाषा गढ़ी थी। गुरु जी ने सभी को एक समान आगे बढ़ने के अवसर देने की नीति को आगे बढ़ाया था। इसी नीति के तहत सबका साथ सबका विकास हरियाणा सरकार के मार्गदर्शन का मूल है। मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि आज हम शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं। परन्तु यह सब गुरु जी के आदर्शों के बिना संभव नहीं होता। उनके विचारों ने हमें न केवल आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि विश्व मंच पर एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कहा कि आज जिस हिंद की चादर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया है, यह शो हरियाणा सरकार का गुरु जी के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनकी शहादत को नई पीढ़ी तक आधुनिक और प्रभावी तरीके से पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस 350वें शहीदी दिवस पर, हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम गुरु तेग बहादुर जी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे।

इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य बलविंद्र सिंह भिंडर व मेजर सिंह गुहला सहित भाजपा नेता यशपाल प्रजापति, मुनीश शर्मा, आयुष गर्ग, अवधेश, प्रवीण प्रजापति, एसडीएम अजय कुमार, रेडक्रास सचिव रामजी लाल, जिला उच्च शिक्षा अधिकार डा. मनोज बांबू, रेडक्रॉस से डा. बीरबल दलाल, संगत के साथ पहुंचे गांव सांगन के सरपंच गुरनाम सिंह, गुरुद्वारा नीमसाहब से मैनेजर हरकीर्तन सिंह, गुरुद्वारा के हैड ग्रंथी साहब सिंह, सतबीर मूंदड़ी, लक्ष्मण बलवंती, मनोज सौंगल, सरपंच प्रतिनिधि सोहन हरिपुरा, श्याम कैथल, सुशील छाबड़ा, हिमांशु गोयल, अशोक मित्तल, डॉ. बलविंद्र संगरोली, सुभाष कुराड़, मोहन, रूपक, विक्की, प्रमोद भाटिया, कृष्ण टीक, कृष्ण सोनी उपस्थित रहे।

लाइट एंड साउंड शो में चंडीगढ़ से आए कलाकारों चरणजीत कौर, बलविंद्र कौर, विक्रमजीत सिंह, हरजोत वीर सिंह, हरप्रीत सिंह हैप्पी, राजेंद्र सिंह, अत्येंद्र पाल सिंह, गुरचरण सिंह, मनजीत सिंह, अक्ष रविंद्र सिंह, रणधीर सिंह, जसबीर सिंह जस्सी, रेशम सिंह, केवल सिंह, हरदीप भुल्लर, पलविंद्र सिंह व गुरजीत सिंह ने पूरी श्रद्धा के साथ गुरु तेग बहादुर के जीवन पर आधारित प्रस्तुति दी।

गांव किठाना में धूम्रपान निषेध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। सीएमओ कैथल डॉ रेनू चावला व एस एम ओ राजौंद डॉ संदीप सिंह के निर्देश अनुसार सीएचसी राजौंद क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। एमपीएचएस कुलदीप ने बताया कि गांव किठाना में धूम्रपान निषेध कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामिणों को समझाया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना कानून विरुद्ध है। नियमों का उलंघन करने वाले व्यक्तियों के चालान काटे गए हैं। टीम ने बताया कि यह कदम लोगों में जागरूकता फैलाने और स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य कर्मी धर्मेंद्र शर्मा और जयभगवान शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाया कि धूम्रपान न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि आस-पास के लोगों के लिए भी हानिकारक होता है। टीम ने ग्रामीणों से अपील की कि वे तंबाकू और धूम्रपान जैसी हानिकारक आदतों से दूर रहें तथा दूसरों को भी इसके दुष्परिणामों के बारें, में जागरूक करें। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल की ग्रामीणों ने सराहना की और भविष्य में ऐसे अभियानों में सहयोग देने का आश्वासन दिया।

'हर घर छत' योजना गरीब व्यक्तियों के लिए वरदान साबित होगी: कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हर घर छत योजना गरीब व्यक्तियों के लिए वरदान साबित होगी। हर घर छत के माध्यम से गरीब व्यक्ति को तुरन्त लाभ मिलें, यही इस योजना का कार्य है।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त श्री पार्थ गुप्ता ने की। कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा पात्र लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कार्यक्रम के बीच-बीच में हर घर छत के पात्र व्यक्तियों के अनुभवों को सुना। उन्होंने कहा कि जनता के कल्याण के लिए ही सरकारें बनती है और जनता के सुझावों से ही सरकार योजनाएं बनाकर उन्हें जनता के लिए लागू करती है। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि वे

जनता के कल्याण के कार्यों में अपनी भूमिका निभाए। उन्होंने इस नेक कार्य के लिए हर घर छत योजना में शामिल जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं सीएसआर के सहयोग के लिए प्रशंसा की।

श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हर घर छत योजना के तहत कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रहें। उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे हर घर छत के तहत पात्र व्यक्तियों के बरसात के समय मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन घरों में अच्छी तरह से कार्य करें, क्योंकि अब मकानों की मुरम्मत करने के लिए समय की अधिकता भी है। जिन मकानों में दरारें हैं, उन मकानों को नीचे से लेकर ऊपर तक बनाए और जिन मकानों की छतें क्षतिग्रस्त हो गई है उनकी छतों की मुरम्मत अच्छी प्रकार से की जाए ताकि गरीब व्यक्ति अपने परिवार सहित आराम से रह सकें।

यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि हर घर छत की पहल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत क्रियान्वित की जा रही है। इससे मानसून के दौरान गरीब परिवारों को होने वाले मानसिक परेशानी से राहत मिलेगी। जिला प्रशासन एवं सीएसआर के सहयोग से जिला में लगभग 40 लाख रुपये की आर्थिक सहायता से 100 पात्र परिवारों के मकानों की छतों एवं मुरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

जिले की मंडियों में अब तक 10 लाख 29 हजार मीट्रिक टन धान की आवक

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। जिला की विभिन्न मंडियों में धान की आमद लगातार जारी है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि अब तक कुल 10 लाख 29 हजार 913 मीट्रिक टन धान की आवक दर्ज की गई है। इनमें से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 6,84,668 मीट्रिक टन, हैफेड ने 2,06,092 मीट्रिक टन तथा हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ने 1,39,153 मीट्रिक टन धान की खरीद की है।

उपायुक्त ने बताया कि मंडियों में धान की खरीद और उठान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। सभी सरकारी खरीद एजेंसियों को समय पर धान उठान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि मंडियों में पारदर्शिता और गति बनाए रखते हुए धान की खरीद और भंडारण कार्य को प्राथमिकता से पूरा किया जाए।

अधिकारी आम जनता द्वारा ऐप पर भेजी शिकायतों को पूर्ण समाधान के बाद ही करे बंद-मुख्यमंत्री

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजेश कुमार

चण्डीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 'म्हारी सड़क ऐप' की कुछ शिकायतों को बिना पूर्ण निवारण के बंद करने और शिकायतों का ठीक से निपटान न करने को लेकर विभिन्न विभागों के सम्बंधित 19 कार्यकारी अभियंताओं पर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इनमें पीडब्ल्यूडी के 2, एचएसएएमबी के 6, एसएसआईआईडीसी के 2, जिला परिषद का 1, यूएलबी के 5 और एसएसवीपी के 3 कार्यकारी अभियंता शामिल है। इसके अलावा, यह भी निर्देश दिए कि जो ठेकेदार तैय समय सीमा में शिकायतों का निवारण नहीं कर रहे हैं, संबंधित विभाग उनके खिलाफ भी कार्यवाही करे। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश आज यहां 'म्हारी सड़क ऐप' पर आई शिकायतों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जो भी कार्य दिया जाता है या लोगों की कोई शिकायत आती है तो उसका समाधान धरातल पर शत प्रतिशत दिखना चाहिए।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अधिकारी आम जनता द्वारा ऐप पर भेजी गई सड़कों की शिकायतों के पूर्ण समाधान के बाद ही शिकायत को बंद करे, यदि किसी शिकायत को संबंधित अधिकारी ने बिना समाधान के बंद किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। साथ ही, प्रदेश की सड़कों पर सफेद पट्टी व साइन बोर्ड लगवाने भी सुनिश्चित किए जाए। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि म्हारी सड़क एप पर शिकायत आते ही उसको तय समय सीमा में पूरा किया जाए ताकि जनता को किसी भी परेशानी का सामना न करना पडें। यदि कोई सम्बंधित अधिकारी शिकायत का समय पर समाधान नहीं करता या गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ सम्बंधित विभाग सख्त कार्यवाही करे। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि म्हारी सड़क ऐप की जानकारी और डाउनलोड करने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा विभिन्न माध्यमों से जागरूक करे, ताकि सड़क से सम्बंधित समस्या को लेकर वें ऐप को उपयोग कर सकें।

इसके अलावा, सडकों के गड्ढों को ठीक प्रकार से भरा जाए, इसको लेकर लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी।